

पटना के श्री वासुदेव अग्रवाल के विरुद्ध आयकर की बकाया राशि

1343. श्री एल० डी० सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना के एक उद्योगपति श्री वासुदेव अग्रवाल पर आयकर की कितनी राशि बकाया है तथा उसकी वसूली के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या उक्त उद्योगपति नकद लाखों रुपये तथा लाखों रुपये के जवाहरात लेकर विदेश जाने का प्रयत्न कर रहा था ; और

(ग) आय कर अधिकारियों ने उस समय जब वह विमान से यात्रा कर रहा था कितना नकद रुपया तथा कितने मूल्य के जवाहरात पकड़े थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) श्री वासुदेव अग्रवाल तथा स्टैंडर्ड मर्केंटाइल कम्पनी, पटना जिसमें वह भागीदार है, की तरफ आयकर तथा दण्ड की बकाया रकम नीचे दिये अनुसार है :—

	आयकर	दण्ड
	रु०	रु०
श्री वासुदेव अग्रवाल	2,10,472	1,07,566
स्टैंडर्ड मर्केंटाइल कम्पनी, पटना	23,58,153	5,74,466

कर की वसूली के लिये प्रमाण-पत्र की कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है। तलाशी के कारणों में से एक कारण करों की वसूली को सुनिश्चित करना भी था।

(ख) जब पटना हवाई अड्डे पर तलाशी ली गई तो वह विदेश जाने के इरादे से पटना से उदयपुर आ रहा था। यह कहना सम्भव नहीं है कि उसका इरादा पकड़ी गयी नकदी,

जवाहरात तथा बहुमूल्य नगीनों को विदेश ले जाने का था अथवा नहीं।

(ग) तलाशी के समय 2,30,000 रुपये की नकदी तथा कई लाख रुपये मूल्य के जवाहरात तथा बहुमूल्य नगीने पकड़े गये।

Fees Charged by Schools in Delhi

1344. SHRI R. P. YADAV : Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) whether there is any uniform pattern of education and levy of schools fees in the different schools of Delhi, including primary, nursery, higher secondary schools ; and

(b) whether Government are aware that some of the privately run schools charge exorbitant fees in Delhi and if so, the steps being taken to make it more reasonable so that the common man may afford it ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI D. P. YADAV) : (a) No, Sir.

(b) Yes, Sir. The Delhi Administration has at present no statutory authority to control the levy of fees by private institutions in Delhi. The Draft Delhi Education Bill proposed to be introduced in Parliament, however, provides for regulating the charge of fees by the recognised schools.

Applications for Credit to Small Borrowers by Nationalised Banks

1345. SHRI KALYANASUNDARAM : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether there had been complaints from small borrowers that their applications for credit were being turned down by the nationalised banks on the plea of shortage of funds, while credit to sectors and units which had been enjoying bank assistance of large sizes for years was not being curtailed ; and